झारखण्ड सरकार
मुख्यमंत्री सचिवालय

प्रेस विज्ञप्ति

राँची,दिनांक– 18.05.16

मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने कहा कि झारखंड चीन के शेंसी प्रांत (Shanxi Province) के साथ ऊर्जा, जल संसाधन एवं खनन के क्षेत्र में सहयोग को इच्छुक है। शेंसी प्रांत की ही तरह भारत के कुल कोयला भंडार का 32 प्रतिशत झारखंड में है। सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए कानूनों में बदलाव कर सरलीकरण किया है। झारखंड में खनन के साथ ही पर्यटन, फूड प्रोसेसिंग, ऑटोमोबाईल, सीमेंट जैसे क्षेत्रों में भी काफी संभावना है। सौर ऊर्जा पर सरकार का विशेष जोर है। उक्त बातें मुख्यमंत्री ने चीन के शेंसी प्रांत के वाइस गवर्नर के नेतृत्व में आये शिष्टमंडल के साथ प्रोजेक्ट भवन में बातचीत के दौरान कही। श्री दास ने स्मार्ट सिटी के निर्माण में सहयोग का भी आग्रह किया। उन्होंने नवंबर 2016 में झारखंड में होने वाले निवेशकों के ग्लोबल समिट में भाग लेने के लिए आमंत्रण भी दिया।

मुख्यमंत्री श्री दास को वाइस गवर्नर श्री गुओ येगुआंग ने सिंतबर में शेंसी प्रांत में होनेवाले एनर्जी एक्सपो में आने का न्योता दिया। साथ ही बताया कि शेंसी प्रांत में अत्याधुनिक तकनीक से कोल उत्खनन का काम किया जाता है। इससे वहां दुर्घटना की दर काफी कम है। शेंसी प्रांत में झारखंड से आधी बारिश होती है, लेकिन वहां 750 जलाशय हैं। इन्हीं के माध्यम से पूरे प्रांत में पानी की आपूर्ति की जाती है। उन्होंने झारखंड के साथ आपसी सहयोग से काम करने की इच्छा जतायी।

बैठक में प्रतिनिधिमण्डल को जानकारी दी गई कि झारखंड में निवेश की अपार संभावनाएं हैं साथ ही सरकार ने बीते एक साल में नीतियों पर बेहतरीन फ्रेमवर्क किया गया है। उन्होंने बताया कि सिंगल विंडो क्लीयरेंस एक्ट–2015, इंडस्ट्रीयल एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी–2015, इंडस्ट्रीयल पार्क पॉलिसी–2015, एक्सपोर्ट पॉलिसी–2015, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पॉलिसी–2015, फीड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पॉलिसी–2015, सहित कुल 11 नीतियों को लागू किया गया। ईज ऑफ डुईंग बिजनेस में पूरे देश में झारखंड को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है जबकि लेबर रिफॉर्म के मामले में झारखंड पूरे देश में अव्वल है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 28 इंडस्ट्रीयल क्षेत्र कार्यरत हैं जहां कई विख्यात उद्योग स्थापित हैं। झारखंड में पूरे देश का 40 फीसदी खनिज भंडार यथा आयरन ओर, कॉपर, यूरेनियम, माइका, क्रोमाईट, कोयला, बॉक्साइट और थोरियम है साथ ही सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न विभागों की नीतियों को सरल बनाया है। झारखंड में मेजर इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर यथा अमृतसर–दिल्ली–कोलकाता इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर, रांची पतरातू–रामगढ़ इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर, कोडरमा–बहरागोड़ा इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर हैं, जो कई शहरों को जोड़ते हैं। वहीं 15 नेशनल हाइ–वे हैं जो राज्य की सीमाओं के अंदर होकर गुजरते हैं। राज्य में कुल 20,311 किलोमीटर का रोड नेटवर्क है वहीं रांची–बोकारो–धनबाद को 6 लेन एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है। इसके अलावा 2182 किलोमीटर का रेल नेटवर्क है साथ ही रांची हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिये कार्यवाई की जा रही है। हर जिले में रन–वे बनाने का भी प्रस्ताव है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की ओर से कॉमन हेल्पलाईन नंबर, सक्षम और संसाधन युक्त जनसंपर्क पदाधिकारी, सिंगल विंडो क्लीयरेंस, ऑनलाईन मॉनिटरिंग , समयबद्ध शिकायतों का निष्पादन सहित विभिन्न तरह की सुविधायें दी जा रही हैं। झारखंड में कुशल श्रम हेतु बीआईटी, आईआईएम, एनआईटी, एक्सएलआरआई, सीयू, एनआईएफएफटी जैसे संस्थान रिसर्च और कार्य कर रहे हैं। साथ ही टूरिज्म के क्षेत्र में कल्चरल टूरिज्म, माइनिंग टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म और इको टूरिज्म के क्षेत्र में सरकार तेजी से कार्य कर रही है। उन्होंने चीन के प्रतिनिधिमंडल को निवेश हेतु आमंत्रित करते हुए कहा कि स्मार्ट सिटी, प्लास्टिक पार्क, फूड एंड फीड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर, टेक्सटाईल्स, मिनरल, ऑटो मोबाइल और इनर्जी के क्षेत्र में निवेश कर सकते हैं।

बैठक में चीन के कोलकाता स्थित काउंसुलेट जेनरल के काउंसुल ली सुयून, झारखंड की मुख्य सचिव श्रीमती राजबाला वर्मा, अपर मुख्य सचिव श्री अमित खरे, उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री यू0पी0 सिंह, जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव श्री सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव श्री सुनील कुमार वर्णवाल समेत अन्य लोग उपस्थित थे।